Tsunami Evaluation Coalition:

Links between relief, rehabilitation and Development in the Tsunami response

सूनामी प्रतिक्रिया सहायता, पुनर्वास व विकास के संदर्भ सहलग्नताए

कार्यकारी सारांश

सहायता की सहलग्नता, पुनर्वास व विकास के संदर्भ में कुल मिलाकर इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि विभिन्न कार्यकर्ताओं के क्रियाकलाप व भूमिका किस प्रकार विचार व अभ्यास से शासित थे एवं इसका निर्धारण करना है कि उन विचारों एवं अभ्यास के क्या परिणाम निकले तथा बाद में अथवा भविष्य में प्रभावित जनसंख्या के लिए क्या कार्य किया गया ।

प्रभावित क्षेत्रों की विकास की प्रक्रिया में, विरोध, जोखिम का नमूना एवं गरीबी के संदर्भ में सूनामी एक अहम पहलू है । अतः बाद में सहायता व विकास के प्रयत्न किए गए थे । यह मूल्यांकन इसका भी अवलोकन करता है कि एसिह व श्रीलंका में किस प्रकार प्रभावित जनसंख्या ने आपदा का सामना किया तथा साथ ही किस प्रकार उन्होंने सहायता उद्योग का सामना किया । यह इसको भी देखता है कि सहायता प्रतिक्रिया को कैसे संबोधित किया गया (और प्रायः उपेक्षित किया गया) श्रीलंका व एसिह में सूनामी से पूर्व क्या हो रहा था । ये वे देश व समुदाय थे जो 26 दिसम्बर, 2004 से पहले विरोध, दीर्घस्थाई गरीबी झेल रहे थे और जहां मानव अधिकार का कोई सम्मान नहीं था ।

प्रारंभ में अति-मत्स्यकरण एक समस्या था, क्योंकि असमानता, आंतरिक विस्थापन था । आपदा ने एलआरआरडी क्रीड़ा का नियम बदल दिया, लेकिन यह क्रीड़ा बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी थी । इस पर जोर देना महत्वपूर्ण है क्योंकि सूनामी प्रतिक्रिया में शामिल एजेंसियां सहायता, पुनर्वास व विकास को एक दूसरे के साथ जोड़ने के निष्पादन कार्य के लिए न तो पूरी तरह से दोषी थीं और न ही पूरी तरह से प्रतिष्ठा प्राप्त थीं । एलआरआरडी को यथार्थ से विश्लेषण करना चाहिए कि सहायता की प्रतिक्रिया किस

प्रकार निरंतर चलने वाली राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक प्रतिक्रयाओं से संबंधित है जिसने प्रभावित जनसंख्या को इस योग्य बनाया कि वे अपना जीवन पुनः शुरू कर सकें ।

सहायता एजेंसियों ने बिल्कुल शुरू से सहायता व पुनर्वास की एक श्रृंखला का आरंभ किया । सहायता व पुनर्वास के कार्य को साथ-साथ चलने की आवश्यकता थी जिसे मान्यता प्राप्त थी व उसी आधार पर कार्य करने की जरूरत थी । सहायता व पुनर्वास के बीच का अंतर पुनर्वास की प्रतिक्रिया में आम रूप से दिखाई दे रहा था जिसे अनिर्धारित बढ़ाए गए कोष व दानदाताओं के लचीलेपन को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया था । सहायता प्रदान करने वाले समुदाय ने प्रारंभिक पुनर्वास की अवस्था में यह सुनिश्चित किया कि प्रभावित जनसंख्या को इतने साधन मिलें कि वह थोड़ी प्रतिष्ठा के साथ रह सके । इस बात ने उन्हें यह सुरक्षा प्रदान कर दी कि उन्हें अपने घरों का पुनःनिर्माण करने व जीवन को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता है । मानव तंत्र ने पहले ही संपत्ति के वितरण जैसे छोटी नाव और मछली पकड़ने का जाल व कार्य के लिए नकदी देने के रूप में जीवन पुनर्वास को समर्थन देना आरंभ कर दिया था । गृह क्षेत्र में पुनर्वास की ओर रूख बहुत धीमा है जब कि यह स्वीकार करने योग्य नहीं है कि प्रभावित जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात आपदा के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी खस्ता हालत वाले टेंट में रह रहा है । आरंभ में यह वायदे किए गए थे कि कुछ ही महीनों में दस हजार घर बना किए जाएंगे । रिकवरी कार्यक्रम के क्या स्वतःस्पष्ट दावे होने चाहिए । इस संदर्भ में इन वायदों का प्रदर्शन गर्व एवं अनभिज्ञता से कर दिया गया था । भवन समुदायों ने भवन बनाने में बहुत लम्बा समय लिया । भूमि अधिकार के मुद्दे, वातावरण के पहलू, सेवाओं व नौकरियों की कड़ी को प्रभावी रूप से संबोधित करने में अनिवार्यतः समय लगता है, लेकिन इसे एलआरआरडी की योजनाओं में इन घोषणाओं की पावती नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप विशेष रूप से एसिह में अंतरवर्ती गृहों के निर्माण में देरी व अपर्याप्तता थी । आपदा से प्रभावित लोगों ने स्थाई घरों के लिए तैयारी व धैर्य दर्शाया, लेकिन वे झूठे वायदों व योजना के असफल होने तथा अंतरवर्ती समय को लम्बा खींचने से क्रुद्ध हो गए । यह परिस्थिति

यह दर्शाती है कि किस प्रकार एजेंसियां प्रभावित लोगों से तृणभूमि के लिए किए गए विशाल वायदे की जबावदेही से हट गई ।

यद्यपि वे तेजी से पुनर्वास की ओर मुखरित हुए थे, अधिकांश सहायता के कार्यकर्ताओं ने सीमित समझ का प्रदर्शन किया । किस प्रकार के हस्तक्षेप जीवनयापन, समुदाय के विकास व साधन प्रबंधन के संदर्भ में अंततः स्थिर साबित होते हैं । मानक पैकेज जैसे छोटी नाव से यह आवश्यक नहीं होता कि वह मत्स्य उद्योग की पुनःस्थापना में योगदान देगी, न ही वह वह विस्तृत निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करती है जिसे ऐसे लोगों के जीवन को सहायोग देने की आवश्यकता है जो तट पर रहते हैं लेकिन छोटे पैमाने के मछुआरे नहीं हैं । कितनी अच्छी तरह से निष्पक्षता का संवर्द्धन किए जाने की संकीर्ण व गलत अवधारणाओं (स्वयं की खेती, मत्स्य कार्य व व्यापार होने को महसूस करना) ने छोटे एवं मध्यम आकार के उपक्रमों में किस प्रकार रोजगार के अवसर खोजने को छोटा कर दिया ।

सूनामी ने सैकड़ों-हजारों लोगों के जीवन का विनाश कर डाला । आर्थिक गतिविधियों ने सूनामी के द्वारा सैकड़ों-हजारों नए जीवनयापन के अवसरों के उत्पन्न करने को प्रेरित किया । उपयोगिता को बढ़ाने व इन दोनों प्रक्रियाओं के अंतर को भरने को, सहायता समुदाय ने इसे नीतिप्रद दृष्टिकोण नहीं माना । पुनर्वास के प्रयास व विस्तृत विकास की प्रवृति की श्रृंखला के मध्य प्रचूर मात्रा में विस्तार से नहीं सोचा गया । इसलिए यह जोखिम रहा कि कुछ पुनर्वास के प्रयास अंततः प्रभावी व अस्थिर सिद्ध हुए । इसके अलावा कुछ में बुरी तरह हस्तक्षेप हुआ, वास्तव में भावी विकास दुर्बल हो चुका था, क्योंकि इन्होनें अति-मत्स्य के कार्य को प्रोत्साहित किया, लघु वित्त संस्थानों की विश्वसनीयता को नष्ट किया तथा अपर्याप्त नियोजित पुनःसमझौते के द्वारा निष्क्रिय समुदायों को उत्पन्न किया ।

प्रभावित जनसंख्या को पुनर्निर्माण की योजनाओं की सूचना न मिलने के कारण उनके स्वयं की एलआरआरडी परियोजनाओं को आरंभ करने की क्षमता सीमित रही । लोगों को अपनी भावी योजनाओं व जीवनयापन के निर्णय की सूचना से अवगत कराने पर भी उन्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि वे कहां रहेंगे तथा क्या प्राप्त करेंगे । सूचना शक्ति है, और सूनामी से प्रभावित लोगों के पास यह नहीं थी ।

इसकी असफलता ने लोगों में सहायता प्रदान करने वालों व सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया । भागीदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों के लिए सहायता व विकास योजनाओं की सूचना प्रारंभिक बिन्दु है जिससे कि वे फैसला की सकें कि वे अपने जीवन को किस प्रकार आरंभ करना चाहते हैं । यह उनका अत्यधिक आधारभूत साधन है जिसके द्वारा वे अपनी सरकार व सहायता प्रदान करने वालों को कब्जे में रखते हैं जिससे उनसे संबंधित सहायता, पुनर्वास व विकास के मध्य श्रृंखला का हिसाब मिल सके । शासकीय व रिकवरी के सामुदायिक स्वामित्व की प्रक्रिया की महत्ता की स्वीकृति लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र द्वारा दी जाती है, लेकिन श्रीलंका के व एजेहन्स संस्थानों में सूनामी प्रतिक्रिया की पकड़ के बारे में निराशा व देरी है । वास्तविक एलआरआरडी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता थी कि वह नीतियों, क्षमताओं व राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के कार्यों को किस प्रकार कार्यक्रम के साथ क्रमबद्ध करें चाहे वे शासकीय हों, नागरिक समाज हो अथवा स्वयं प्रभावित जनसंख्या । राष्ट्रीय व स्थानीय संस्थानों की दुर्बलता विचारणीय थी, अतः संरेखण को एक लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता थी, परन्तु समग्र कार्यवाही को कायम रखने की आवश्यकता थी । कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि अब यह प्रारंभ होना हो चुका है । लेकिन कुछ इलाकों में कर्मचारियों के अतिक्रमण व पूर्ववर्ती नीति के ढांचे की ओर अपर्याप्त ध्यान के कारण महत्वपूर्ण क्षति हो चुकी थी । अधिकांश एजेंसियों ने इन दो देशों की ऐतिहासिक प्रवृति की अनभिज्ञता दर्शाई एवं सहायता के कार्यक्रम किस प्रकार विगत त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं तथा विकास अवसरों में योगदान कर सकते हैं । जटिल व्यापार को बंद करने को गति व गुणवत्ता की प्रतिक्रिया और इस बात का फैसला करने कि लोगों को कहां रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे भविष्य में आपदा का जोखिम कम हो सके, के बारे में मतैक्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने वाले समुदाय व सरकारों ने कठिन व समय लगने वाली प्रक्रिया के रूप में अनुभव किया । अंतर्रोधी मण्डल के विषय में अनबन व भ्रम ने सहायता समुदाय को राष्ट्रीय राजनैतिक प्रक्रियाओं से दूर कर दिया । इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि जोखिम को कम करने के बिंदुओं की ओर ध्यान देने में कमी हो गई ।

श्रीलंका व एसिह में विरोध के प्रक्षेप-पथ पर सहायता के पहलू का निर्धारण करना कठिन है । सूनामी ने श्रीलंका में शान्ति लाने में मदद नहीं की । फिर भी इसने इसमें पहले शालीन धनात्मक प्रभाव किए जिसकी संभवतः त्रासदी के बाद की परार्थोन्मुखता तथा सूनामी के कारण हुई सैन्य क्षति संबंधी दो वजह थीं । प्रारंभिक आपातकालीन अवस्था के पश्चात आनुवंशिक संघर्ष पर सहायता संसाधनों को नियंत्रित करने का बिन्दु प्रोत्साहन देने से अधिक तार्किक हो गया । इस रिपोर्ट को लिखने के समय (दिसम्बर 2005) होने वाली हिंसा में वृद्धि को सूनामी प्रतिक्रिया के श्रेय के रूप में सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन सहायता प्रवाह पर प्रतियोगिता व तत्पश्चात अविश्वास को ऋणात्मक पहलू माना जा सकता है ।

इंडोनेशिया के पास बहुत पृथक प्रक्षेप-पथ था । एसिह में जिस तेजी से विरोधों/झगड़ों को सुलझा लिया गया उसकी सूनामी से पूर्व आशा नहीं थी । फिर भी सहायता प्रतिक्रिया व शान्ति समझौते के मध्य आकस्मिकता के किसी भी अनुमान को सावधानी से लेना चाहिए, बहुत से एसिहवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस शुरूआत व सहायता उपस्थिति को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जो इस अचानक आए परिवर्तन का समर्थन कर रहा था । झगड़ों/विरोधों की गत्यात्मकता पर सूनामी के धनात्मक पहलू के अलावा शान्ति समझौतों के अन्य आश्चर्यजनक धनात्मक प्रभाव थे जो स्वयं में हिंसा की कमी से अधिक महत्वपूर्ण थे । युद्धरत पक्षों ने अनौपचारिक करों को कम कर दिया, क्षेत्रों की ओर अभिगमन में सुधार किया, लोगों के जमाव के नियमों में ढील दी, नागरिक समाज के पुनरोत्थान को स्वीकृति दी और सामान्य रूप से अधिक धनात्मक दृष्टिकोण प्रकट हुआ ।

एलआरआरडी कलाकृति की प्रक्रिया नहीं है । यह आपदा से प्रभावित देश व समुदायों की राजनैतिक अर्थव्यवस्था के ज्ञन की मांग करता है । यह क्षेत्रीय स्तर पर सीखने की क्षमता व तत्परता की मांग भी करता है । एजेंसियां स्थानीय संस्थानों के साथ प्रासंगिक ज्ञान व संबंध बनाने में अपर्याप्त रूप से अग्रसक्रिय रहीं । बिना पूर्व निर्णित उपलब्ध धन की मात्रा को प्रभावित जनसंख्या के संदर्भ से अधिक इस चिन्ता की प्रवृति के रूप में लिया गया कि 'गृह पृष्ठ' की क्रिया कैसी दिखेगी । कुल मिलाकर भावी उलझाव यह है कि सहायता प्रावधानों पर एकाग्र केंद्रीय परियोजनाओं को एकाएक आरंभ करने की

आवश्यकता है जिससे सहायता, पुनर्वास व विकास के मध्य महत्वपूर्ण श्रृंखला की प्राप्ति हो जिन्हें प्रभावित जनसंख्या ने स्वय, राष्ट्रीय जनता व निजी संस्थानों ने बनाया है जिनके आधार पर वे नौकरियों, सेवाओं व मानव सुरक्षा के लिए आश्रित हैं । सूनामी से प्रभावित लोगों ने कुछ समय सहायता समुदाय की अव्यवस्थित व बेध्यानी वाली कार्य योजनाओं की ओर प्रस्थान किया । इस प्रकार एलआरआरडी कार्य योजनाओं में सुधार ऐजेंसियों का मामला नहीं था जो जीवनयापन अथवा गृह निर्माण के रूप में अच्छा बना । यह इस गहन विश्लेषण के स्थान पर है कि 'हमारे' थोड़े प्रयास किस प्रकार 'उनके' एलआरआरडी परियोजनाओं के समर्थन में योगदान दे सकते हैं ।

'उनके एलआरआरडी में परियोजनाओं' के ध्यान ने अनिवार्य रूप से लघु व बृहत राजनैतिक प्रक्रियाओं में अत्यधिक व्यस्तता का आरंभ किया । इसने कुछ ऐसी मानवीय एजेंसियों के मध्य एक न्यायसंगत असुविधा को जन्म दिया जो इस बात से संबंधित थी कि तटस्थता के मानवीय सिद्धांतों को कैसे दृढ़ रूप में कायम रखा जाए । प्रभावी एलआरआरडी स्वतंत्रता की अनुवर्ती हानि के द्वारा स्थानीय संस्थानों के साथ नजदीकी व्यवस्तता की मांग करता है । राजनैतिक व्यावहारिक ज्ञान, प्रतिबद्धता की स्पष्टता व प्रासंगिक जागरूकता द्वारा तथापित कमजोर पड़े मानवीय सिद्धांतों के कुछ पहलुओं में संतुलन बनाया जा सकता है जिससे विरोध की स्थिति में निष्पक्षता व तटस्थता एव संसाधनों के प्रवाह को प्रभावित करने वाले राजनैतिक प्रयासों के बीच सुनिश्चितता हो । पुनर्वास समर्थन के प्रावधानों में भौगोलिक असंतुलन(विशेष रूप से श्रीलंका में) ने बहुत सी एजेंसियों पर मानवीय सिद्धांतों को कायम रखने की योग्यता पर प्रश्न उठाए हैं । श्रीलंका व एसिह में कर्मचारियों के सीमित अनुभव के प्राधान्य ने चिन्ता जताई है कि उनके पास एलआरआरडी की लघु राजनैतिक वास्तविकताओं के युक्तिचालन का अनिवार्य कौशल नहीं है ।

इस मूल्यांकन में सम्पूर्ण दो निष्कर्षों के प्रति चिन्ता जताई है । पहला, एलआरआरडी के लिए, अभी और अधिक प्रभावी होना है, स्थानीय व राष्ट्रीय विकास की प्रक्रियाओं में लगने के लिए सहायता उद्योग को अधिक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है । यह पुनर्निर्माण के कार्य तथा राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर संस्थानों के साथ रचनात्मक ढंग से कार्य करने के तरीकों की अग्रसक्रिय खोज को विश्वासी प्राप्ति है ।

दूसरे, कई एजेंसियों में एलआरआरडी के कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से लेने की क्षमता में कमी है । राष्ट्रीय प्राधिकरणों व दानदाताओं को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि एजेंसियां जिम्मेदारियों का विभाजन न करें, ऐसी जिम्मेदारियां कौशल की विश्वासी हैं उन्हें वे स्पष्टतः एकत्र नहीं कर सकते ।

अनुशंसाएं

एलआरआरडी को अधिक दृढ़ता से राष्ट्रीय व स्थानीय संदर्भ की प्रक्रियाओं के मूल में लेना चाहिए - सहायता की कार्ययोजनाओं व प्रभावित जनसंख्या की पहल के वर्तमान वर्गीकरण के बीच सेतुबंधन के लिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी कि राष्ट्रीय प्राधिकरणों के एलआरआरडी कार्यसूची, स्थानीय कर्मचारियों, एनजीओ, व्यवसायों व प्रभावित जनसंख्या में सहायता किस प्रकार योगदान करती है अथवा उनमें बाधा डालती है ।

सहायता व पुनर्वास के बीच श्रृंखला प्राप्त कर ली गई लेकिन लम्बे समय के विकास के कार्यक्रमों की उलझनों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । अर्थव्यवस्था की क्रियाओं को पुनः शुरू करने के लिए सहायता एकमात्र नहीं है और प्राथमिक यंत्र भी नहीं है । अतः सहायता हस्तक्षेप की सफलताओं व असफलताओं के श्रेय के बारे में सावधानी रखना अधिक महत्वपूर्ण है । फिर भी सहायता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित बहुत से लोगों के जीवनयापन की व्यवहार्यता संदेहजनक है । पुनःनिर्मित व उत्पन्न हुई समुदायों की कार्यशीलता पर बिना पर्याप्त ध्यान दिए आश्रय को प्रायः संकीर्ण यथार्थ के रूप में संबोधित किया जाता है । ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां स्थिर प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग, विरोध व आपदा जोखिम के कार्यक्रमों की उलझनों का अपर्याप्त निर्धारण किया जाता है ।

गरीबी उपशमन, हस्तक्षेपों के लिए आवश्यक है कि उन्हें चल रहे उपशमन प्रक्षेप-पथ के साथ संबंधित माना जाए - दीर्घकालीन व अस्थाई गरीबी को काबू करने के लिए प्रभावी व स्पष्ट एलआरआरडी स्वयं में प्रयासों का विवेकपूर्ण संतुलन है । सूनामी द्वारा उत्पन्न अस्थाई गरीबी के उपशमन में प्रगति बहुत तेजी से हुई । फिर भी अभी ऐसे लोगों का महत्वपूर्ण अनुपात है जिनकी सूनामी संबंधी अभावग्रस्तता ने उन्हें दीर्घकालीन

गरीबी की श्रेणी में ला दिया । उनकी असंभाव्य रूप से छोटी संपत्तियों के प्रतिस्थापन द्वारा मदद की गई । उनकी आवश्यकताओं को आर्थिक विकास व/अथवा सामाजिक सुरक्षा द्वारा अधिक अच्छे ढंग से संबोधित किया गया । इस प्रकार न ही इन तत्वों ने सूनामी प्रतिक्रिया को दूर तक एकीकृत रूप से प्रभावित किया

प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने की आवश्यकता अधिक विचारणीय है और सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत इसकी रणनीति बनाने की आवश्यकता है - अतिरक्ति अंतर्राष्ट्रीय ध्यान व पूर्ववत चेतावनियों के लिए धन देने के बावजूद, जोखिम में कमी को रिकवरी कार्यक्रम की मुख्यधारा में नहीं लाया गया । वातावरण व राष्ट्रीय संसाधनों के सहायता कार्य के पहलूओं पर गहरे व प्रमाणिक निर्धारण की आवश्यकता है । इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार के आघातों जो राष्ट्रीय खतरों, विरोधों व अन्य कारकों से आए, उनका सामना करने के लिए राष्ट्रीय ढांचे पर किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली जाए । सरकारों को समर्थन देने के लिए सहायता को पुनः केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नागरिकों की सुरक्षा, जीविका व प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती हैं ।

प्रभावित जनसंख्या पर एलआरआरडी के प्रयासों की श्रृंखला को मजबूत सूचना प्रवाह के माध्यम से सुधारना चाहिए । आपदा से प्रभावित लोगों को इसकी सूचना देने की आवश्यकता है कि उन्हें क्या सहायता मिलेगी जिससे वे निर्णय ले सकें कि वे कितनी अच्छी तरह से अपने जीवन व जीवनयापन का पुनःनिर्माण कर सकते हैं । एलआरआरडी परियोजनाओं पर आगे बढ़ने वाली प्रभावित जनसंख्या के प्रयासों में सहायता की परियोजनाओं में भाग लेना गौण है । उन्हें पर्याप्त सूचना नहीं मिली अतः उनका क्रोध, हताशा व भ्रम न्यायसंगत है । अच्छी सूचना का प्रावधान विनीत बना सकता था लेकिन एलआरआरडी की कार्यसूची को प्रभावित करने के लिए प्रभावित जनसंख्या की पेबन मजबूती में अधिक योगदान दिया गया । सहायता, पुनर्वास व विकास को एक साथ लाने के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय व घरेलू प्रयासरों का समर्थन करना चाहिए जिससे नीतियों व कार्यप्रणाली में श्रृंखला बन सके । अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व वैयक्तिक एजेंसियां जो सूनामी प्रतिक्रिया में शामिल थीं उनके पास सहायता, पुनर्वास व विकास को श्रृंखलाबद्ध करने के लिए

कोई बड़ी योजना नहीं थी । उन्हें एक की आवश्यकता नहीं है । उनकी जिम्मेदारी सहायता समर्थन, राष्ट्रीय एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रयास के मध्य श्रृंखला को सुनिश्चित करना है । रिकवरी सहायता विखंडन की प्रवृति व दुर्बल सहयोग का अर्थ है कि अधिकांश एजेंसियों के पास कोई विकल्प नहीं है और उन्हें अपनी एलआरआरडी परियोजनाओं पर ही एकाग्र होना पड़ेगा जो ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होंगे जिनमें सहायता से विकास की ओर जाने के लिए स्पष्ट दबाव है एवं परिणाम दुखद हैं । आपदा से प्रभावित जनसंख्या के लिए आश्रय व जीवनयापन पर ध्यान देना प्राथमिक है, इन क्षेत्रों में एलआरआरडी के सहायता सुधारों की संभाव्यता अधिक थी ।

कौन क्या करने योग्य है और कब, इस बारे में एलआरआरडी को अच्छी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया गया । एलआरआरडी में जिन समस्याओं पर जोर दिया गया वे प्रायः उनसे संबंधित हैं जिनमें एजेंसियों ने बहुत अधिक वायदे किए लेकिन कार्य बहुत थोड़ा किया । एजेंसियों, दानकर्ताओं व सरकारी प्राधिकरणों ने ऐसे वायदे करने के लिए दबाव डालने का अनुभव किया जो उन कार्यों के लिए थे जो उनकी पहुंच से दूर थे । इसलिए यह जरूरी नहीं कि आलोचना इन उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता से होनी चाहिए, अपितु उन तरीकों से होनी चाहिए जिन्होंने प्रभावित जनसंख्या से किए गए दावों को पूरा न होने वाला वायदा व विकास योजनाओं में अल्पमार्ग को निष्क्रिय कर दिया ।